नईदुनिया

वारसॉ में प्रदर्शन, राष्ट्रपति का विमान बीच रास्ते से लौटा

पोलैंड में प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क पर तख्ता पलट की कोशिश का आरोप

वारसॉ, एजेंसीः पोलैंड में प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश का आरोप लगा है। विवाद देश के संवैधानिक न्यायाधिकरण के नेतृत्व को लेकर शुरू हुआ। शुक्रवार को न्यायाधिकरण की एक न्यायाधीश ने अध्यक्ष बोगदान श्विएंत्सकोव्स्की और उपाध्यक्ष बार्तलोमिए सोचान्स्की को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने की घोषणा की।

फैसले के विरोध में सैकड़ों लोग न्यायाधिकरण के बाहर जमा हुए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर वस्तुएं फेंकीं। हालात बिगड़ने के बीच राष्ट्रपति कारोल नावरोत्स्की सेनेगल जाते समय बीच रास्ते से लौट आए। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में राष्ट्रपति का देश में रहना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री टस्क और राष्ट्रपति

नावरोत्स्की के बीच न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा न्यायपालिका के कामकाज को लेकर लंबे समय से मतभेद हैं।

टस्क का आरोप है कि पिछली सरकार ने अदालतों में अपने समर्थकों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर की। राष्ट्रपति का कहना है कि सरकार के कदम संविधान के अनुरूप होने चाहिए।

विवाद की शुरुआत 2015 में हुई थी, जब कानून एवं न्याय पार्टी की सरकार ने न्यायपालिका में कई बदलाव किए। इनमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु घटाना, अदालतों के प्रमुखों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बढ़ाना और न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई की अलग व्यवस्था बनाना शामिल था। विपक्ष और यूरोपीय संघ ने इन बदलावों का विरोध किया था। 2023 में टस्क की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। उसने न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराने और कानून का शासन बहाल करने का वादा किया। हालांकि, पिछली सरकार के समय नियुक्त कई न्यायाधीश अब भी महत्वपूर्ण पदों पर हैं।

इस वर्ष मार्च में संसद ने संवैधानिक न्यायाधिकरण के लिए छह नए न्यायाधीश चुने। राष्ट्रपति ने इनमें से केवल दो को शपथ दिलाई। शेष चार ने 9 अप्रैल को संसद में शपथ ली, लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय और न्यायाधिकरण के प्रमुख ने इसे मान्यता नहीं दी। उन्हें अदालत में काम करने की अनुमति भी नहीं मिली।

शुक्रवार को न्यायाधीश अन्ना कोर्विन-पियोत्रोव्स्का ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निलंबित करने का आदेश दिया। उनका कहना था कि नए न्यायाधीशों को काम से रोकने के कारण न्यायाधिकरण का काम प्रभावित हो रहा था। विपक्ष ने इस कदम को अवैध बताते हुए कहा कि अन्ना को नेतृत्व संभालने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री टस्क ने सरकार के फैसलों का बचाव करते हुए कहा कि पिछली सरकार के शासन में कानून का उल्लंघन हुआ था। उनके अनुसार, कानून का शासन बहाल करना कठिन प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

यमुना में तैराकी करेंगे किरेन रिजिजू और मनोज तिवारी

तिवारी ने नदी में डुबकी लगाकर प्रदूषण घटने का दावा किया, रिजिजू ने तैराकी प्रतियोगिता का दिया प्रस्ताव

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी को नदी में तैराकी प्रतियोगिता की चुनौती दी है। तिवारी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दोनों के बीच मुकाबले के लिए तारीख तय करने की बात कही। यह विवाद तब चर्चा में आया, जब मनोज तिवारी ने गुरुवार को दिल्ली के सोनिया विहार के पास यमुना में डुबकी लगाई। उन्होंने नदी का पानी पीने का दावा भी किया और कहा कि पिछले एक वर्ष में यमुना का प्रदूषण आधा हो गया है। तिवारी ने नदी की सफाई के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लोग फिर से यमुना तट पर छठ पूजा मना सकेंगे। तिवारी के इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए रिजिजू ने सामाजिक माध्यम पर लिखा कि यमुना का पानी पहले से बेहतर हुआ है और दोनों के बीच तैराकी प्रतियोगिता हो सकती है। इसके जवाब में तिवारी ने कहा कि वह चुनौती स्वीकार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तैराकी में रिजिजू को हराना आसान नहीं होगा, लेकिन दिल्ली की साफ यमुना में उनके साथ मुकाबला करना अच्छा अनुभव होगा। तिवारी ने अपने संदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को भी यमुना में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित किया था। वहीं, आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई को लेकर भाजपा के दावों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने तिवारी और दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा को कालिंदी कुंज घाट पर आकर नदी का पानी पीने की चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि नदी के कुछ हिस्सों में अब भी प्रदूषण बना हुआ है।

अमेरिका यूक्रेन को 500 पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलें बेचेगा

वाशिंगटन, एजेंसीः अमेरिका ने यूक्रेन को 500 पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलें बेचने की संभावित योजना को मंजूरी दे दी है। इस सौदे की अनुमानित कीमत करीब 19 हजार करोड़ रुपये बताई गई है। इसका पूरा खर्च यूरोपीय देश और कनाडा उठाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के हमलों से बचाव के लिए हर महीने 100 मिसाइलें उपलब्ध कराने की मांग की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को इस संभावित सौदे को मंजूरी दी। इसके तहत यूक्रेन को पैट्रियट प्रणाली की आधुनिक पीएसी-3 एमएसई मिसाइलें मिलेंगी। ये मिसाइलें हवा में ही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम हैं। जेलेंस्की ने अमेरिकी मंजूरी का स्वागत किया, लेकिन कहा कि मौजूदा शर्तों के अनुसार मिसाइलों की आपूर्ति शुरू होने में कई वर्ष लग सकते हैं। उन्होंने अमेरिका से जल्द आपूर्ति का रास्ता निकालने की अपील की। सामाजिक माध्यम पर उन्होंने कहा कि 500 मिसाइलें सर्दियों में यूक्रेन की हवाई सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं,

लेकिन रूस के हमलों का खतरा अभी बना हुआ है।

जेलेंस्की के अनुसार, अक्टूबर के पिछले दो सप्ताह में रूस ने यूक्रेन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर 30 से अधिक हमले किए। उनका आरोप है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सर्दियों से पहले यूक्रेन की आवश्यक सेवाओं को ठप करना चाहते हैं। रूसी हमलों में बिजली व्यवस्था, घरों को गर्म रखने की सुविधाएं, जलापूर्ति और पुलों को निशाना बनाया जा रहा है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिका, यूरोपीय देशों और अन्य सहयोगियों से अपने मौजूदा मिसाइल भंडार में से तत्काल सहायता देने का सुझाव दिया। उनके अनुसार, बाद में नई मिसाइलों का उत्पादन कर सहयोगी देशों के भंडार की भरपाई की जा सकती है। इससे 2026-27 की सर्दियों में यूक्रेन को आवश्यक सुरक्षा मिल सकेगी। इस बीच, 29 अक्टूबर को रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन के निप्रो शहर के रेलवे स्टेशन पर 14 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई थी।

ढाका में तारिक रहमान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

नेशनल सिटिजन पार्टी की रैली में महंगाई, बिजली और ईंधन संकट पर उठे सवाल; गृह और ऊर्जा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग

ढाका, एजेंसीः बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर भारत विरोधी नारे लगाए गए। नेशनल सिटिजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में शुक्रवार को राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने बड़ी रैली हुई। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई, बिजली संकट और ईंधन तथा गैस की कमी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद तथा ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद के इस्तीफे की मांग की।

रैली के दौरान सामाजिक माध्यमों पर सामने आए दृश्यों में नाहिद इस्लाम और अन्य नेताओं को 'दिल्ली नहीं, ढाका' के नारे लगाते देखा गया। इसके जवाब में भीड़ ने 'ढाका, ढाका' के नारे लगाए। नाहिद इस्लाम वर्ष 2024 के जुलाई आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं, जिसके बाद शेख हसीना की सरकार सत्ता

से बाहर हो गई थी। रैली को संबोधित करते हुए नाहिद इस्लाम ने भारत पर बांग्लादेश के मामलों में हस्तक्षेप और साजिश के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार बांग्लादेश को कथित भारतीय साजिशों से सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं है। उन्होंने सीमा पर लोगों की मौत, असम और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के साथ भेदभाव तथा दिल्ली में मस्जिदों को गिराने की योजना होने जैसे आरोप भी लगाए।

नाहिद ने भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा समझौते का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यदि इस समझौते पर निष्पक्ष तरीके से दोबारा बातचीत नहीं हुई तो बांग्लादेश के लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे। यह समझौता दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है।

घरेलू संकट से बढ़ी नाराजगी

रैली में नेशनल सिटिजन पार्टी के सांसद हसनत अब्दुल्ला भी शामिल हुए। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से बिजली और गैस की कमी बनी हुई है। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। देश अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत से अधिक तेल और लगभग 30 प्रतिशत गैस आयात करता है। बिजली कटौती का असर कपड़ा उद्योग पर भी पड़ा है। महंगाई ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। नाहिद इस्लाम ने चेतावनी दी कि मंत्रियों के इस्तीफे और अन्य मांगें पूरी नहीं होने पर देशव्यापी प्रदर्शन किए जाएंगे।

बिहार में भाजपा को मजबूती, दो निर्दलीय विधान पार्षद पार्टी में शामिल हो गए

राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी ने थामा भाजपा का दामन

नईदुनिया ब्यूरो, पटनाः बिहार की राजनीति में शनिवार को महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। हाल ही में विधान परिषद चुनाव जीतने वाले दो निर्दलीय विधान पार्षद राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दोनों नेताओं के पार्टी में आने से बिहार विधान परिषद में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले राहुल राज पहले भाजपा से जुड़े रहे थे।

उन्होंने चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी आनंद पुष्कर को हराया था। इसके बाद भाजपा ने उन्हें छह वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब उनकी पार्टी में वापसी हुई है। भाजपा में शामिल होने से पहले

राहुल राज ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। इस दौरान सारण के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद रहे। राहुल राज ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों की मांगें और समस्याएं रखीं। मुख्यमंत्री ने इन पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है।

शक्तिशाली देश के उपप्रधानमंत्री बेटी को हिंदी फिल्मों में काम दिलाना चाहते हैं: पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री ने भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहचान का उल्लेख करते हुए सुनाया किस्सा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिंदी फिल्म उद्योग की वैश्विक लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक के उपप्रधानमंत्री उनकी लगातार मदद मांग रहे हैं। उनकी बेटी हिंदी फिल्म उद्योग में काम करना चाहती है। गोयल ने यह बात शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित विचार महोत्सव के चौथे संस्करण में कही। भारतीय उत्पादों और वैश्विक पहचान से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए गोयल ने कहा कि यह मानना गलत है कि भारत के पास वैश्विक पहचान वाले ब्रांड नहीं हैं। उन्होंने कहा कि टाटा और महिंद्रा जैसे उद्योग समूहों के अलावा हिंदी फिल्म उद्योग भी भारत की बड़ी सांस्कृतिक पहचान है। गोयल ने कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग अब दुनिया भर में पहचाना जाने वाला ब्रांड बन चुका है। इसकी लोकप्रियता का उदाहरण देते हुए उन्होंने विदेशी उपप्रधानमंत्री से जुड़ा किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि दुनिया के एक शक्तिशाली देश के उपप्रधानमंत्री उनके पीछे पड़े हैं, क्योंकि उनकी बेटी हिंदी फिल्मों के साथ काम करना चाहती है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने संबंधित देश और उपप्रधानमंत्री का नाम उजागर नहीं किया। गोयल के इस बयान पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने तंज कसा। उन्होंने सवाल किया कि क्या गोयल भारतीय जनता पार्टी में अपनी राजनीतिक भूमिका के बाद के भविष्य के लिए अवसर तलाश रहे हैं।

हूती विद्रोहियों ने अदन में राष्ट्रपति भवन पर दागीं दो मिसाइलें

सना, एजेंसीः यमन के हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार को अदन स्थित राष्ट्रपति भवन पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हालांकि, मिसाइलें अपने लक्ष्य पर लगीं या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। समाचार एजेंसी के अनुसार, हमले के बाद राष्ट्रपति भवन की ओर एंबुलेंस जाती दिखाई दीं। यमन सरकार के सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि हूती विद्रोहियों ने अदन हवाई अड्डे को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। हालांकि, उन्होंने हमले में किसी के मारे जाने या घायल होने की जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति भवन परिसर पर 15 दिन में यह दूसरा हमला है। इससे पहले 15 अक्टूबर को पांच बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हमले में चार लोगों की मौत हुई थी और परिसर को काफी नुकसान पहुंचा था। अदन यमन की अंतरराष्ट्रीय

स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का प्रमुख केंद्र है। हूती विद्रोहियों ने 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सरकार को सना छोड़ना पड़ा। जुलाई से अदन में हमले फिर बढ़े हैं। 28 अक्टूबर को भी हूतियों ने अदन हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। यह दक्षिणी यमन में राहत सामग्री और मानवीय सहायता पहुंचाने का महत्वपूर्ण मार्ग है।

लंदन में पढ़ाई कर रही मुग्धा पुणे के फ्लैट में मृत मिलीं

नईदुनिया ब्यूरो, पुणेः महाराष्ट्र के पुणे जिले में 34 वर्षीय मुग्धा देशमुख की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु का मामला सामने आया है। उनका शव गहुंजे क्षेत्र की लोढ़ा बेलमोंडो आवासीय सोसायटी स्थित किराए के फ्लैट में मिला। परिवार को लगता था कि मुग्धा लंदन में प्रबंधन की पढ़ाई कर रही हैं, जबकि पुलिस के अनुसार वह अगस्त में ही भारत लौट आई थीं।

छत्रपति संभाजीनगर निवासी मुग्धा जुलाई 2025 में प्रबंधन की पढ़ाई के लिए लंदन गई थीं। वहां वह कुछ समय अंशकालिक काम भी करती थीं और नियमित रूप से माता-पिता के संपर्क में रहती थीं। 23 अक्टूबर को उन्होंने अपनी मां से फोन पर बात की थी। उन्होंने बताया था कि वह एक साक्षात्कार के लिए जा रही हैं। इसके बाद 24 अक्टूबर से उनका फोन बंद आने लगा। परिवार ने लंदन में रहने वाली उनकी सहेली से संपर्क किया। सहेली ने लंदन पुलिस से जानकारी ली, जहां पता चला कि मुग्धा अगस्त में ही ब्रिटेन छोड़ चुकी थीं।

विरोधाभास *नई रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं रोज पुरुषों से लगभग पांच घंटे अधिक घरेलू काम करती हैं, वेतन और विश्राम में भी अंतर*

महिलाओं की संख्या दोगुनी, लेकिन घर के काम का बोझ अब भी बरकरार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या पिछले आठ वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है, लेकिन घर के काम और देखभाल की जिम्मेदारियों का बंटवारा अब भी असमान बना हुआ है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद की 'भागीदारी का विरोधाभास' नामक रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ने के बावजूद उन्हें नौकरी के साथ घरेलू जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ रही हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2017-18 में भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या 10.4 करोड़ थी, जो 2025 में बढ़कर 20.1 करोड़ हो गई। इस अवधि में कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत पहुंची। ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि अधिक रही। वहां महिलाओं की भागीदारी 23.7 प्रतिशत से बढ़कर 44.9 प्रतिशत हुई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 18.2 प्रतिशत से बढ़कर 25.9 प्रतिशत रही। हालांकि, रोजगार में बढ़ती भागीदारी के साथ घरेलू कामों में पुरुषों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया। आंकड़ों के अनुसार, महिलाएं प्रतिदिन औसतन 464 मिनट घरेलू काम करती हैं, जबकि पुरुषों का

समय 178 मिनट है। इस तरह महिलाएं रोज लगभग चार घंटे 46 मिनट अधिक घरेलू जिम्मेदारियां निभाती हैं। घरेलू काम और बच्चों की देखभाल महिलाओं के रोजगार में बड़ी बाधा बने हुए हैं। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 60 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि इन जिम्मेदारियों के कारण वे घर से बाहर नौकरी नहीं कर पातीं। पुरुषों में ऐसा कहने वालों की संख्या केवल एक प्रतिशत रही। रिपोर्ट में वेतन का अंतर भी सामने आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कमाई पुरुषों की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 61 प्रतिशत है।